ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

ब्रजगोपाल , प्रोफ़ेसर मोहम्मद शाहिद , (2025)

शीत युद्ध के बाद भारत की ईरान नीति: संतुलन, चुनौतियाँ और रणनीतिक स्वायत्तता

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड रिव्यूज़, 4(3), 127-141.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

शीत युद्ध के बाद भारत की ईरान नीति: संतुलन, चुनौतियाँ और रणनीतिक स्वायत्तता

[1] ब्रजगोपाल
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

[2] प्रोफ़ेसर मोहम्मद शाहिद
शोध मार्गदर्शक
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

How to Cite the Article:

ब्रजगोपाल , प्रोफ़ेसर मोहम्मद शाहिद ,(2025), शीत युद्ध के बाद भारत की ईरान नीति: संतुलन, चुनौतियाँ और रणनीतिक स्वायत्तता .*इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड रिव्यूज़, 4(3), 127-141.*

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v4i3.2025.127-141

सूचक शब

भारत-ईरान संबंध,

शीत युद्ध के बाद की विदेश नीति,

रणनीतिक स्वायत्तता,

बहु-संरेखण

1 सार

१९९१ में शीत युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया एक बहुध्रुवीय दौर में प्रवेश कर गई, जहाँ कई देश वैश्विक शक्ति केंद्र बन कर उभरे। इस बदलाव ने भारत की विदेश नीति को गहरे तौर पर प्रभावित किया है खासकर ईरान के साथ उसके सम्बंधों को। ईरान भारत के लिए ऊर्जा, क्षेत्रीय संपर्क और बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने का एक अहम साझेदार रहा है। यह अध्ययन १९९१ से २०२५ तक भारत-ईरान सम्बंधों के विकास को समझाता है। इसमें सरकारी रिकॉर्ड, नीतिगत दस्तावेज़ों और शोध कार्यों का विश्लेषण किया गया है १९९० के दशक के शुरुआती समझौतों से लेकर चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी हाल की परियोजनाओं तक। अध्ययन बताता है कि भारत ने बड़ी सावधानी से अपने सम्बंधों का संतुलन बनाए रखा है। उसने एक ओर अमेरिका के प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय वोटिंग जैसी स्थितियों को संभाला है, वहीं दूसरी ओर इज़रायल, खाड़ी देशों और ईरान के साथ भी सम्बंध को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। भारत ने चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे मंचों का भी इस्तेमाल किया है। हालाँकि अमेरिका के प्रतिबंधों की वज़ह से तेल व्यापार और चाबहार बंदरगाह परियोजना प्रभावित हुई हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और २०२५ में बढ़े इज़रायल-ईरान तनाव ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया है। फिर भी भारत ने अपनी स्वतंत्र और व्यावहारिक नीति से कई लाभ हासिल किए हैं—जैसे INSTC के जरिए यूरेशिया तक ४०% तेज़ व्यापार मार्ग। अंत में यह अध्ययन सुझाव देता है कि भारत को कई देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी चाहिए। इससे वह बदलते वैश्विक माहौल में गुटनिरपेक्षता के आधुनिक और लचीले रूप को मज़बूत कर सकेगा। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

2. प्रस्तावना

अंतरराष्ट्रीय सम्बंध दुनिया भर के लोगों और संस्कृतियों से सम्बंधित हैं। इन समूहों के बीच बातचीत की जटिलता का दायरा अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों को एक चुनौतीपूर्ण विषय बनाता है (गोल्डस्टीन, २००६)[1]। नवयथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद उन कई व्याख्याओं में से एक है जो अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों में समकालीन सैद्धांतिक बहस पर हावी हैं। संरचनात्मक यथार्थवाद एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संरचना के महत्त्व और राज्य के व्यवहार के प्राथमिक निर्धारक के रूप में इसकी भूमिका पर ज़ोर देता है।

भारत और ईरान एशिया के दो सबसे पुराने देश हैं जिनकी अलग-अलग विशिष्ट संस्कृतियाँ और निरंतर संपर्क रहा है। पश्चिम एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में ईरान के उभरने के साथ भारतीय नेताओं ने भारत-ईरान सम्बंधों के रणनीतिक महत्त्व पर ज़ोर दिया है। हालांकि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और पूर्व सोवियत संघ के साथ इसके घनिष्ठ सम्बंध और सेंटो में ईरान की सदस्यता और अमेरिका के साथ इसके गठबंधन ने शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों को अलग-अलग दिशाओं में खींच लिया जिससे पहलवी राजवंश के दौरान उनके राजनीतिक हित एवं द्वीपक्षीय सम्बंध प्रभावित हुए।

१९७९ की इस्लामिक क्रांति के साथ द्विपक्षीय सम्बंधों में बदलाव आया है। भारत ने इस्लामिक क्रांति की सकारात्मक शर्तों में ईरान की स्वतंत्रता और आत्म-दावे की खोज और महाशक्ति प्रभाव के बिना एक स्वतंत्र विकास करने के प्रयास के प्रतिबिंब के रूप में देखा। इस दौरान ईरान के नवीन राजनीतिक ढांचे ने न पूर्व न पश्चिम की नीति का पालन किया जिससे द्विपक्षीय सम्बंधों में सुधार हुआ गौरतलब है कि पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण सम्बंधों ने भारत को प्राकृतिक गैस और खनिज समृद्ध मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक भारत की जमीनी पहुँच को अवरुद्ध कर दिया है जबकि वैश्विक प्रतिबंधों के कारण ईरान के ऊर्जा संसाधनों तक उसकी पहुँच बाधित हुई है। हालांकि प्रतिबंधों की संभावित समाप्ति के साथ भारत ईरान के साथ बातचीत के माध्यम से चुनौतियों से पार पाने की उम्मीद करता है। दूसरी ओर स्वायत्तता के लिए ईरान की खोज अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ इसके जुड़ाव को बाधित करती है जो अपने विदेशी सम्बंधों में प्रभुत्व चाहते हैं और भारत को एक मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं (कुमार, २०१६)[2] भारतीय प्रधान मंत्री की हाल की ईरान यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और ईरान ऊर्जा क्षेत्र में एक-दूसरे के पूरक हैं और अफगानिस्तान को स्थिर करने और संसाधन संपन्न मध्य एशिया को हिंद महासागर से जोड़ने में रुचि रखते हैं।

3. बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत-ईरान के संबंध

भारत सरकार के आकलन और जनमत इस बात से सहमत हैं कि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव, चीन-भारत सीमा पर इसकी बढ़ती सैन्य आक्रामकता (विशेष रूप से २०२० से) और पाकिस्तान के लिए इसका समर्थन, जो भारत को लक्षित करने वाले आतंकवादी समूहों को शरण प्रदान करता है, इसे अल्पावधि में देश का सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बनाता है (डेवलिन, 2019: 13[3]; पंत एच वी ,2021: 20-1[4]) अमेरिका के साथ भारत की समकालीन समय में विकसित साझेदारी चीन की इस चुनौती को कम करने की उसकी रणनीति के केंद्र के रूप में उभरी है। साथ ही दूसरी तरफ़ नई दिल्ली आर्थिक और व्यापारिक पहलों पर ईरान की सौदेबाजी की रणनीतियों से भारतीय नेतृत्व को निराश किया है, साथ ही मध्य पूर्व में उसके व्यवहार के कारण दंडात्मक अमेरिकी नीतियाँ (आर्थिक प्रतिबंध) भी सामने आई हैं-इन सभी के कारण ईरान के साथ वैध व्यापार करना एवं भारतीय हितों को सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो गया है। भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के संपन्न होने के १५

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

साल से अधिक समय बाद भी ईरान पर भारत के रुख को उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता के पालन के 'लिटमस टेस्ट' के रूप में देखा जाता है (ओल्लापल्ली और राजगोपालन 2012: 101[5]) ।यद्यपि ईरान निश्चित रूप से भारत के लिए उपयोगी साबित हुआ है-चाहे वह या तो चीनी परियोजनाओं के विकल्पों पर काम करने का एक तरीक़ा हो, उदाहरण के लिए, चाबहार बंदरगाह (बनाम ग्वादर का पाकिस्तानी बंदरगाह) , या अफगानिस्तान की तरह अपने साझा पड़ोस में पाकिस्तान के रणनीतिक प्रभाव (या गहराई) का मुकाबला करना हो। भारत-खाड़ी और भारत-इजरायल सम्बंधों में शुद्ध सकारात्मक वृद्धि ईरान के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में खाई को व्यापक बनाती है जिससे बहुध्रुवीय झुकाव लिए वि श्व प्रभावी स्थिति के लिए नई दिल्ली की खोज में ईरान की भूमिका और उपयोगिता पर सवाल उठते हैं।

एक बदलती वि श्व व्यवस्था मध्यम से दीर्घावधि में भारत के लिए अवसर लाती है। वास्तविकता यह है कि भारत की रणनीतियों को आज वैश्विक व्यवस्था में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी रणनीति के आसपास की अनिश्चितता से लाभ हुआ है, जो ट्रम्प युग में अधिक स्पष्ट हो गया है (मुखर्जी, 2020: 12-14)[9] ।भारतीय नीति निर्माताओं ने यह पहचानने में जल्दबाजी की कि ट्रम्प की भव्य रणनीति 'क्षणिक अभिव्यक्ति नहीं थी' (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 2017)[10] और यह कि एक विभाजित अमेरिकी प्रतिष्ठान ने भारत को वाशिंगटन की प्राथमिकताओं के साथ पैंतरेबाज़ी करने के लिए अधिक जगह दी है (मोहन, 2017)[11] ।बहुध्रुवीयता पर टिकी वि श्व व्यवस्था ने भारत के लिए न केवल अमेरिका, बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस के माध्यम से रणनीतिक समर्थन हासिल करने के साथ-साथ चीन को शामिल करने के अवसर खोल दिए हैं। भारत ने बाद में इंडो-पैसिफिक में अपने लिए एक नई भूमिका बनाई है, जिसमें अधिक लचीले रणनीतिक परिदृश्य में अधिक आसानी से शामिल है। अपने लाभ के लिए इस लचीलेपन का लाभ उठाकर, भारत ने ईरान के साथ अपने सम्बंधों में अधिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया है, ईरान के अधिकारियों के साथ साझा चिंता के मामलों पर लगातार परामर्श किया है, जैसे कि तालिबान की वापसी के साथ अफगानिस्तान में अस्थिरता का नया खतरा।

4. रणनीतिक असंगति

रणनीतिक स्तर पर, भारत ने अमेरिकी हितों के साथ साझा समानता पाई है और शीत युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उदय को महत्त्व देते हुए अमेरिका के साथ घनिष्ठ सम्बंध बनाने की इच्छा दिखाई है। यह अब अमेरिका का एक प्रमुख रक्षा भागीदार है और अमेरिका और उसके सहयोगियों, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में एक प्रमुख भागीदार है। दूसरी ओर, ईरान को बढ़ता अमेरिकी आधिपत्य समस्याग्रस्त लगता है और उसने इस तरह के आधिपत्य का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से विविध सम्बंध बनाए हैं, उदाहरण के लिए, चीन और रूस के साथ। परिणामस्वरूप भारत-ईरान सम्बंधों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका और ईरान अपनी प्रतिद्वंद्विता से कैसे निपटते हैं। दंडात्मक अमेरिकी नीतियों और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत की योजनाओं को जटिल बना दिया है और यदि हालिया समय में इस दिशा में और अधिक तनाव बढ़ता है तो संभावित रूप से मामले कुछ हद तक नई दिल्ली के सीधे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। ईरान का विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम एक दूसरा मुद्दा है जो भारत के लिए मामलों को और जटिल बनाता है क्योंकि वह महाशक्ति का दर्जा हासिल कर रहा है। नई दिल्ली का मानना है कि अप्रसार पर इसकी त्रुटिहीन साख ने इसे अच्छी स्थिति में रखा और वाशिंगटन द्वारा सुगम विशेष

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

परिस्थितियों का नेतृत्व किया, जिसने इसे एनपीटी के बाहर एक परमाणु हथियार राज्य के रूप में वैधता प्रदान की (बसरूर और सुलिवन डी एस्ट्राडा, २०१७)[12] ।लगातार भारत की सरकारों ने ईरान के वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवहार के प्रबंधन के सम्बंध में मध्यस्थता या सीमित हस्तक्षेप दृष्टिकोण अपनाया है। इसने हमेशा कूटनीति का आह्वान किया है क्योंकि सैन्य संघर्ष उसके पड़ोस और ऊर्जा सुरक्षा सहित महत्त्वपूर्ण हितों को अस्थिर कर देगा।

तीसरी महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक चुनौती यह है कि भारत की ईरान रणनीति में चीन द्वारा पेश किया गया है और ईरान के साथ उसके सम्बंधों पर इसका गहन प्रभाव है। यद्यपि भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती आर्थिक पकड़, जैसे कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और प्रतिबंधों के कारण बीजिंग पर ईरान की पर्याप्त आर्थिक निर्भरता दो महत्त्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने भारत और ईरान को २०१५ में चाबहार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक-दूसरे की ओर धकेल दिया (नारायणन कुट्टी, 2016)[13] ।२०२० में ईरान ने चीन के साथ जिस नई रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, वह ईरान में अपने सीमित प्रभाव को देखते हुए भारत को नुक़सान पहुँचाती है, यहाँ तक कि विशेषज्ञों ने संदर्भ और सामग्री दोनों में चीन के रणनीतिक आलिंगन को अधिक आंकने के खिलाफ चेतावनी दी है (ग्रीर और बैटमैनघेलिज, 2020)[14] ।हालांकि, इसकी घोषणा के समय ने नई दिल्ली में कड़ी चिंता पैदा कर दी थी क्योंकि यह मई २०२० में चीन की सीमा पर झड़पों के ठीक बाद आया था जो बेहद महत्त्वपूर्ण थे और चीन के बारे में भारत के आकलन को फिर से परिभाषित करते थे।

5. क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को अलग करना

क्षेत्रीय स्तर पर भारत-ईरान सम्बंध अफगानिस्तान की स्थिति और अरब खाड़ी देशों और इज़राइल दोनों के साथ ईरान की प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित होती है, जिसमें भारत की आंतरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव भी शामिल है। पहला भारत ईरान को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रणनीतिक प्रभाव के प्रतिकार के रूप में देखता है, यह देखते हुए कि कोई भी देश विशेष रूप से सुन्नी बहुल सरकार नहीं देखना चाहता है। हालांकि यह दृष्टिकोण २००१ के बाद से विकसित हुआ है, जब उन्होंने संयुक्त रूप से तालिबान को बाहर कर दिया था। भारत ने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में एक स्थिर उपस्थिति के रूप में देखा, जिसने अपनी नीतियों का समर्थन करने में मदद की, जबकि ईरान ने अमेरिका को अफगान अस्थिरता में योगदान देने और समस्या के हिस्से के रूप में देखा (बरजेगर, 2014[15]; नारायणन कुट्टी, 2014[16]) ।इसका जवाब देने के लिए ईरान ने तालिबान के कुछ गुटों के

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

साथ सम्बंध बनाए, जो उसके हितों के अनुकूल थे और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकते थे। (वर्मा, 2022)[17] यहाँ यह प्रासंगिक है कि पाकिस्तान के साथ ईरान की द्विपक्षीय बातचीत उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में 'नियंत्रित शत्रुता' के प्रमुख अपवाद के साथ उदार बनी हुई है (वटंका, 2015)[18] अमेरिका के बाहर निकलने और तालिबान की बाद की वापसी के साथ भारत ने खुद को ईरान के साथ गहन बातचीत में वापस पाया है, मध्य पूर्व में ईरान के प्रतिद्वंद्वियों, यानी अरब खाड़ी देशों और इज़राइल के साथ भारत का बढ़ता रणनीतिक अभिसरण उनके बीच क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को अलग करने का दूसरा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता के कारण भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवाद के लिए वैचारिक प्राथमिकता, मध्य पूर्व में विभिन्न शक्ति केंद्रों के साथ जुड़ाव को आगे बढ़ाने के रास्ते में नहीं आई है (मोहन, सीआर, 2020)[19] अरब खाड़ी राज्यों के साथ, उनकी सरकार ने अपने पूर्ववर्तियों के काम पर निर्माण किया है, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। पाकिस्तान के साथ पारंपरिक निकटता के बावजूद, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारत की ओर एक पूरक झुकाव से इसे और अधिक सक्रिय किया गया है। खाड़ी देशों ने भी भारत में ईरानी कच्चे तेल के आयात के नुक़सान से पैदा हुई कमी को भरने के लिए तत्परता दिखाई, जब ट्रम्प के तहत प्रतिबंध वापस आ गए। इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) जैसे क्षेत्रीय मंचों के भीतर अरब खाडी देशों के बढते प्रभाव ने बाद में इस क्षेत्र (पहले पाकिस्तान द्वारा निर्देशित) के भीतर भारत की स्थिति में परेशानियों को दूर करने में मदद की। अरब खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग ८ मिलियन नागरिकों के साथ, भारत आज ईरान और वहाँ भारतीयों के घटते समुदाय की तुलना में अपनी खाड़ी साझेदारी पर बहुत अधिक निर्भर कर रहा है (विदेश मंत्रालय, 2017)[20]। लोगों से लोगों के बीच मज़बूत सम्बंध और बिजनेस-टू-बिजनेस (बी२बी) सम्बंध आज भारत-खाड़ी सम्बंध को संचालित करते हैं, जबकि ईरान के बारे में स्थिति इसके विपरीत है, जहाँ दोनों सरकारों को अपने दम पर भारी काम करना पड़ता है। मध्य पूर्व में भारत के एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार के रूप में इजरायल के उभरने के लिए मज़बूत बी२बी सहयोग भी ज़िम्मेदार है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग इजरायल के साथ द्विपक्षीय बातचीत में सबसे ऊपर है, यह ध्यान में रखते हुए कि यह भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। मोदी सरकार ने इज़राइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधान मंत्री बनकर इस सम्बंध की दृश्यता को बढ़ाया, जो ईरान के लिए बहुत नाराजगी बाला था (चौबे, 2017)[21]

अंत में, भारतीय हितों को उनके साझा पड़ोस में ईरान के व्यवहार से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया है (पालीवाल, 2017: 272;[22] नारायणन कुट्टी, 2019: 103)[23]। ऐसी ही एक घटना में २०११ में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारतीय मदद से बनाए गए सलमा बाँध (अब अफगान-भारत मैत्री बाँध) में तोड़फोड़ करने के ईरानी प्रयास शामिल थे। दूसरा २०१२ में नई दिल्ली में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) द्वारा प्रायोजित बमबारी थी, जिसमें इजरायली राजनयिकों को निशाना बनाया गया था। हाल ही में, विदेशी जहाजों को जब्त करके होर्मुज जलडमरूमध्य (अमेरिकी दबाव के जवाब में) में समुद्री व्यापार को बाधित करने के ईरान के प्रयासों-उदाहरण के लिए, २०१९ में स्टेना इम्पेरो और एमटी / रियाह-ने अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार को असुविधा पहुँचाई, क्योंकि इन जहाजों पर चालक दल के अधिकांश सदस्य भारतीय थे (द वीक, 2019[24]) इस तरह की घटनाएँ भारत को इस क्षेत्र में ईरान के साथ काम करने के सम्बंध में व्यापक जाल बिछाने से रोकती हैं।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

ब्रजगोपाल , प्रोफ़ेसर मोहम्मद शाहिद , (2025)

शीत युद्ध के बाद भारत की ईरान नीति: संतुलन, चुनौतियाँ और रणनीतिक स्वायत्तता

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड रिव्यूज़, 4(3), 127-141.

6. द्विपक्षीय और घरेलू चुनौतियां

जैसा कि एक नया स्वतंत्र भारत वैश्विक मंच पर अपनी विदेश नीति को तैयार करने के लिए तैयार हो रहा था, 1949 में भारतीय राजनयिकों के बीच तीव्र अटकलें थींकि ईरान, अपने आश्वासन के बावजूद, उन तीन देशों में से एक था जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर-स्थायी सदस्यता के लिए भारत के खिलाफ मतदान किया था। नई दिल्ली को एक स्पष्ट संदेश में, ईरानी मामलों के जानकार एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि वह 'ईरानी वादों से कतराते रहे हैं और उन पर कार्रवाई करने के बाद ही उन पर भरोसा करेंगे' (भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, 1949)[25] ईरान के प्रस्तावों के इस प्रारंभिक मूल्यांकन का तात्पर्य एक अंतर्निहित विश्वास की कमी से है, जो आज तक उनके द्विपक्षीय जुड़ाव पर मंडरा रहा है। उदाहरण के लिए, अनुकूल परिस्थितियों में भी उनकी द्विपक्षीय सम्बंधों की तीव्रता कम रही है। २०१५ में, भारत ने ईरान और पी५+१ राज्यों के बीच जेसीपीओए (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी को संदर्भित करता है) के बीच प्रतिबंधों से राहत की खिड़की का स्वागत किया। ईरानी परमाणु समझौता 'कूटनीति और दूरदर्शिता की जीत' था और इसने भारत और ईरान के लिए लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रगति करने का एक गंभीर अवसर प्रस्तुत किया, जैसे कि चाबहार बंदरगाह का विकास और फरजाद-बी गैस सौदा (विदेश मंत्रालय, 2016)[26] इन परियोजनाओं ने सीमित प्रगति की है या इससे भी बदतर, फरजाद-बी गैस सौदे की तरह, लगभग एक दशक तक कई दौर की बातचीत के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चाबहार पर, देरी ने भारतीय पक्ष को निराशा व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया कि 'बहुत सारी समस्याएँ इसलिए थीं क्योंकि ईरानियों ने समझौते की शर्तों को बदलना जारी रखा' (पेरी, 2018)[17] इस द्विपक्षीय संबंधों की आर्थिक क्षमता काफी हद तक अवास्तविक रही है, हाल के वर्षों में गैर-तेल, गैर-स्वीकृत व्यापार भी बंद हो गया है।

भारतीय पक्ष की ओर से विचार का दूसरा घरेलू बिंदु इसकी घरेलू शिया आबादी, यानी 200 मिलियन भारतीय मुसलमानों का 15 प्रतिशत (भारत की जनगणना, 2011)[28] का सऊदी अरब जैसी अन्य मध्य पूर्वी शक्तियों के साथ इस संबंध और जुड़ाव पर प्रभाव है। इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि ईरान के साथ इस निर्वाचन क्षेत्र के धार्मिक संबंधों का चुनावी प्रभाव है, यह देखते हुए कि विदेश नीति (राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों से अलग. जैसे कि पाकिस्तान के साथ सीमा पार की समस्याएं) भारतीय आम चनावों में एक छोटी भूमिका निभाती है (कपूर, 2009)[29] हालाँकि, ईरान की हालिया घटनाओं का असर भारत में भी ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी हमले में आईआरजीसी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद, नई दिल्ली, कश्मीर (कारगिल) और देश के अन्य हिस्सों में कई अमेरिका विरोधी प्रदर्शन हुए। (मोहन, जी., 2020[30]; तस्नीम न्यूज एजेंसी, 2020)[31] सुलेमानी की मृत्यु के तुरंत बाद नई दिल्ली का दौरा करने वाले ईरानी विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ ने एक स्पष्ट रूप से सुविचारित टिप्पणी की कि अमेरिका को 'अन्य शहरों में हमारी [ईरान] पहुंच को समझना चाहिए' (बसु, 2020)[32] भारतीय घरेलू राजनीति और आंतरिक स्थिरता पर इसके निश्चित प्रभाव को देखते हुए यह इस चर्चा के लिए एक नया और विकसित महत्व का स्थान है।

7. भारत और ईरान: राजनीतिक संबंध

पश्चिम एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में ईरान के उभरने के साथ, भारतीय नेताओं ने भारत-ईरान सम्बंधों के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर दिया। हालांकि, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और पूर्व सोवियत संघ के साथ इसके

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

घनिष्ठ सम्बंध और सेंटो में ईरान की सदस्यता और अमेरिका के साथ इसके गठबंधन ने शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों को अलग-अलग दिशाओं में खींच लिया, जिससे पहले पहलवी राजवंश के दौरान शीत युद्ध के दौरान उनके राजनीतिक हित प्रभावित हुए। १९७९ की क्रांति के साथ द्विपक्षीय सम्बंधों में बदलाव आया है। भारत ने क्रांति को ईरान की स्वतंत्रता और आत्म-दावे की खोज और प्रमुख शक्ति प्रभाव के बिना एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम लेने के प्रयास के प्रतिबिंब के रूप में देखा (तिरुपति, 2014)[33] ।यह १९९३ में भारतीय प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव, १९९५ में ईरानी राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी और १९९६ में भारत के उपराष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन की उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान द्वारा चिह्नित किया गया है। २००१ में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की यात्राओं और २००३ में राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी की वापसी यात्रा के साथ इस प्रवृत्ति को बढ़ाया गया था। ईरान के राष्ट्रपति डॉ. महमूद अहमदइनेजाद ने २००८ में भारत की यात्रा की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमानी से मुलाकात की। २०१२ में, डॉ. अली अकबर विलायती ने भारत का दौरा किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वित्त मंत्री जरीफ ने २०१४ और २०१५ में भारत का दौरा किया था। २०१६ में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. हसन रूहानी से मुलाकात की थी। भारतीय प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति ने तेहरान में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने 'सभ्यतागत संपर्क, समकालीन संदर्भ' शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेन् द्र मोदी और ईरान के राष् ट्रपति हसन रूहानी के बीच शिष् टमंडल स् तर की वार्ता के बाद इन समझौतों और समझौतों पर हस् ताक्षर किए गए। भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के निर्माण और संचालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में १२ समझौता ज्ञापन (एमओयू) और समझौते।

8. भारत और ईरान: आर्थिक संबंध

भारत और ईरान ऊर्जा क्षेत्र में एक-दूसरे के पूरक हैं और अफगानिस्तान को स्थिर करने और संसाधन संपन्न मध्य एशिया को हिंद महासागर से जोड़ने में रुचि रखते हैं। दक्षिण-पूर्वी ईरान में चाबहार बंदरगाह एक परिवहन गलियारे के रूप में काम कर सकता है जो इसे अफगानिस्तान, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से जोड़ता है जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए एक वैकल्पिक पहुँच मार्ग प्रदान करेगा। यह गलियारा उनके बड़े पड़ोसियों की तुलना में उनकी सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करेगा और भारत को ऊर्जा और खनिज समृद्ध क्षेत्र तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान को बायपास करने में सक्षम बनाएगा। चाबहार बंदरगाह, चाबहार मुक्त व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र भी ईरान को एक क्षेत्रीय व्यापार, विनिर्माण और ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरने में मदद कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वायत्तता के लिए तेहरान की खोज अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ इसके जुड़ाव को बाधित करती है जो अपने विदेशी सम्बंधों में प्रभुत्व चाहते हैं। यह बदले में भारत को ईरान के साथ द्विपक्षीय सम्बंधों में एक मूल्यवान उद्घाटन प्रदान करता है जिसका उपयोग आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण मध्य एशिया तक पहुँचने के लिए किया जा सकता है (कुमार, 2016)[34]

ऊर्जा का भविष्य का विकास महत्त्वपूर्ण रूप से उन स्रोतों से बढ़ती मात्रा में इसकी दीर्घकालिक उपलब्धता पर निर्भर करता है जो भरोसेमंद, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ हैं। वर्तमान में, इस भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई स्रोत हाथ में नहीं है। जीवाश्म ईंधन (तेल, गैस और कोयला) दुनिया

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

भर में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं, जो कुल विश्व ऊर्जा खपत का ८६% हिस्सा हैं और अगले तीन दशकों तक ऐसा ही रहेगा। हालांकि, तेल की खपत ३८% से घटकर ३३% होने की उम्मीद है, जबकि गैस और कोयले की खपत क्रमशः २४% से बढ़कर २६% और २७% हो जाएगी। अगर कीमतें अधिक रहती हैं तो तेल की मांग में और गिरावट आ सकती है। इस स्थिति में प्राकृतिक गैस २१वीं सदी का ईंधन बन जाती है, जो तेल से सस्ती और कोयले की तुलना में स्वच्छ होती है (नासिरपुर, 2016)[15]

ईरान एक ऊर्जा महाशक्ति है और ईरान में पेट्रोलियम उद्योग इसमें एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जून २०१६ में ब्रिटिश पेट्रोलियम रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के अनुसार, ईरान में साबित तेल भंडार, २०१६ तक लगभग १५७ बिलियन बैरल (२४×१०९ एम ३) के साथ दुनिया में चौथा सबसे बड़ा स्थान है (ब्रिटिश पेट्रोलियम, २०१६) , हालांकि यह तीसरे स्थान पर है यदि अपरंपरागत तेल के कनाडाई भंडार को बाहर रखा जाता है। यह दुनिया के कुल सिद्ध पेट्रोलियम भंडार का लगभग १०% है। उत्पादन की २००६ की दरों पर, ईरान का तेल भंडार ९८ वर्षों तक चलेगा यदि कोई नया तेल नहीं मिला (विकिपीडिया, 2016)[16]

शिपिंग डेटा के अनुसार, ईरान 2016 में प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ईरान से भारत का तेल आयात इस साल बढ़ गया है, जब उसके परमाणु विकास कार्यक्रम पर प्रतिबंध, जो निर्यात को सीमित करता है, जनवरी में हटा लिया गया था (महाजा, 2016)[17] जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ऑपरेटर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित भारतीय रिफाइनर, जिन्होंने प्रतिबंधों की अवधि के दौरान ईरान से आयात बंद कर दिया था, वे भी ईरानी तेल के खरीदारों के रूप में वापस आ गए हैं (वर्मा, 2016)[18]

बीपी रिपोर्ट (समीक्षा, 2016)[39] के अनुसार, ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार है, जो 33.8 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर या दुनिया के कुल सिद्ध भंडार का 18.2 प्रतिशत है। भारत प्रति दिन लगभग 80 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है, लेकिन घरेलू मांग प्रति दिन 170 एमसीएम है। इस प्रकार, भारत को प्रति दिन लगभग 90 एमसीएम आयात करना होगा। ऊर्जा सलाहकार वुड मैकेंजी के अनुसार, प्राकृतिक गैस की भारतीय मांग प्रति वर्ष 8 प्रतिशत बढ़ रही है और 2020 तक 270 एमसीएम प्रति दिन तक पहुंच जाएगी।

१९९० के मध्य से भारत और ईरानी अधिकारी २७०० किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए बातचीत में शामिल रहे थे-जिसे ईरान-पाकिस्तान-भारत (आईपीआई) पाइपलाइन परियोजना के रूप में भी जाना जाता है-जो ईरान में दक्षिण पार क्षेत्र से लेकर भारत में गुजरात तक फैली हुई है, जिसकी अनुमानित क़ीमत ७ बिलियन डॉलर है। दोनों देशों के लिए गैस के सबसे सुविधाजनक आपूर्तिकर्ता के रूप में, ईरान ने

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

पाइपलाइन की निर्माण लागत का ६० प्रतिशत कवर करने की भी पेशकश की। २००७ में, भारत और पाकिस्तान गैस की ब्रिटिश थर्मल यूनिट के लिए $ ४.९३ के आधार मूल्य का भुगतान करने पर सहमत हुए।

आईपीआई की विफलता के बावजूद, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राकृतिक गैस निर्यात करने की ईरान की महत्वाकांक्षा जीवित और अच्छी तरह से है। भारतीय और ईरानी अधिकारियों ने समुद्र के नीचे पाइपलाइन के माध्यम से ओमान और भारत को ईरानी प्राकृतिक गैस निर्यात करने के लिए एक विशाल परियोजना को शुरू करने के लिए गंभीर बातचीत फिर से शुरू की। इस विकास से पहले महीनों तक गहन चर्चा हुई है। २०१४ में, भारतीय उद्योग परिसंघ के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष, श्रीकांत सोमानी ने ओमान चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक संयुक्त बैठक में कहा कि ईरानियों के साथ समुद्र के नीचे की परियोजना में तेजी लाई जानी चाहिए। इसके बाद नवंबर में नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी के प्रमुख अलीरेजा कामेली ने ईरानी मीडिया को बताया कि तेहरान इस तरह की ईरान-भारत पाइपलाइन के निर्माण के लिए नई दिल्ली के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है। दो हफ्ते बाद, ९ दिसम्बर, २०१५ को ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अपनी भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों ने अपने देशों के आपसी आर्थिक सहयोग का विस्तार करने की संभावना पर चर्चा की, विशेष रूप से ईरान द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात करने के सम्बंध में। इसके बाद, २८ दिसम्बर, २०१५ को ईरान के आर्थिक मामलों और वित्त मंत्री ने स्वराज से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए एक ७३ अनुच्छेद समझौते पर हस्ताक्षर किए और विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में (येगनेहशाकिब, 2016)[40]

चाबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है, जो पाकिस्तान के मकरान तट का विस्तार है, जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के साथ हिंद महासागर के संगम के करीब है। इस बंदरगाह को ईरान ने मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया है। यह पाकिस्तान के समान रूप से महत्वपूर्ण चीन द्वारा वित्त पोषित ग्वादर बंदरगाह से लगभग ७० किमी पश्चिम में स्थित है। इस बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति अफगानिस्तान से व्यापार की आवाजाही के लिए उपयुक्त है, जो एक भूमि से घिरा हुआ देश है। जैसा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ आर्थिक और रणनीतिक रूप से जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक था, यह चाबहार बंदरगाह को काबुल के लिए एक आसान समुद्री-भूमि मार्ग के रूप में देखता है। इस विकल्प ने और अधिक महत्व प्राप्त कर लिया क्योंकि पाकिस्तान ने पंजाब में वाघा सीमा के माध्यम से अफगानिस्तान को भारतीय व्यापार के लिए भूमि मार्ग प्रदान करने से इनकार कर दिया (सोढ़ी, 2015)[41] भारत ईरान में महत्वपूर्ण निवेशक के रूप में उभरा है, और ईरान के निर्मित सामानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य के रूप में भी उभरा है (रघुरामपत्रुनी, 2014)[42] मई 2016 में, भारत और ईरान ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत चाबहार बंदरगाह में से एक का नवीनीकरण करेगा, और बंदरगाह पर 600 मीटर लंबी कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का पुनर्निर्माण करेगा। यह बंदरगाह भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा। इसमें 2.5 मिलियन टन (गार्जियन, 2016)[43] को संभालने की क्षमता है।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

प्रस्तावित ईरान-अफगानिस्तान सड़क नेटवर्क, चाबहार-मिलक-जरांज-दिलाराम, का उपयोग अफगानिस्तान के गारलैंड राजमार्ग पर व्यापार के परिवहन के लिए किया जाएगा। भारत पहले ही अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में २२० किलोमीटर सड़क के निर्माण पर १०० मिलियन यूडीएस खर्च कर चुका है। इस परियोजना के पूरा होने पर, नेटवर्क अफगानिस्तान के चार प्रमुख शहरों, हेरात, कंधार, काबुल और मजार-ए-शरीफ तक आसान पहुँच प्रदान करेगा। इस प्रकार, भारत के व्यापार को मध्य एशिया के संसाधन समृद्ध क्षेत्र से स्पष्ट मार्ग मिल सकता है। भारत ९०० किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने की योजना को भी अंतिम रूप दे रहा है जो चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में खनिज समृद्ध हाजीगक क्षेत्र से जोड़ेगी। इस रेलवे नेटवर्क की उपलब्धता भारत को ऊर्जा समृद्ध मध्य एशियाई राज्यों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के साथ एक लिंक भी प्रदान करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग है। कॉरिडोर का उद्देश्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान, बंदर अंजली आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार संपर्क को बढ़ाना है। २०१४ में दो मार्गों के ड्राई रन आयोजित किए गए थे, पहला मुंबई से बाकू वाया बंदर अब्बास और दूसरा मुंबई से अस्त्रखान वाया बंदर अब्बास, तेहरान और बंदर अंजली (विकिपीडिया, 2016) था[44]।
नया आईएनएसटीसी लिंक शुरू में परिवहन के समय को लगभग 20 दिन और बाद में 14 दिन तक कम कर देगा। यह भारत से मध्य एशिया और अफगानिस्तान के लिए एक छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय मार्ग खोलेगा। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईईयू) वर्तमान में मुक्त व्यापार समझौते की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहे हैं। नया लिंक भारत को ईईयू (जफर, 2016)[45] से भी जोड़ता है।

9. सहयोग की बाधाएं

9.1 भारत-इजरायल

भारत-इजरायल सम्बंध भारत के साथ ईरान के सम्बंधों को बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं कर सके। उदाहरण के लिए वे हमेशा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपने मतभेदों को दूर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ईरान के साथ हाल ही में छह-शक्ति समझौते पर इजरायल और भारत में अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दो दीर्घकालिक साझेदारों के बीच रणनीतिक मतभेद के एकमात्र बिंदु को उजागर करती हैं। हालांकि इजरायल जिनेवा एक्शन प्लान और ईरान के साथ संभावित व्यापक अंतरराष्ट्रीय मेल-मिलाप से संतुष्ट नहीं है, लेकिन भारत ने सतर्क आशावाद के साथ इसका स्वागत किया है। आम तौर पर, जबकि इजरायल ईरान की परमाणु मुद्रा को एक अस्तित्व के खतरे के रूप में देखता है, भारत इसे तेहरान में नई दिल्ली की रणनीतिक प्रोफ़ाइल को बढ़ाने के लिए एक भू-राजनीतिक बाधा के रूप में अधिक देखता है और ईरान पर अमेरिकी वित्तीय प्रतिबंधों की हालिया अवधि के दौरान भी, इस्लामी गणराज्य भारत के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बना रहा।

ईरानी सरकार जानती है कि हर राज्य अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने की कोशिश करता है और इस तरह इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि किसी भी अन्य राज्य की तरह भारत की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हित पर

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

आधारित है। २००२ में भारतीय वाणिज्य सचिव द्वारा ईरान की यात्रा के दौरान ईरानी सरकार को यह स्पष्ट कर दिया गया था जब उन्होंने कहा था कि "भारत इजरायल सहित सभी राज्यों के साथ अच्छे सम्बंधों का समर्थन करेगा" (जरगर; 2007, 173)[46] हालांकि ईरानी सरकार ने भारत-इजरायल सम्बंधों के विस्तार पर अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन उसने भारत के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक सम्बंधों को काटने या कम करने की इच्छा नहीं दिखाई है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बंधों को विकसित करने के उद्देश्य से ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ की हालिया भारत यात्रा को इसी के प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के साथ घनिष्ठ सम्बंध बनाए रखने में भारत के महत्त्वपूर्ण हित हैं, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा की बढ़ती महत्त्वपूर्ण आवश्यकता ने नई दिल्ली को वाशिंगटन द्वारा दृढ़ता से विरोधी घोषित किए गए शासनों के साथ सम्बंधों को बढ़ावा देने के लिए मजबूर किया है। इस दुविधा का महत्त्व ईरान के साथ भारत के सम्बंधों में स्पष्ट है, जो एक प्रमुख क्षेत्रीय ऊर्जा-उत्पादक और संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल का कट्टर विरोधी है। जैसे-जैसे भारत एक प्रभावशाली वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए अपनी आर्थिक और औद्योगिक क्षमता का निर्माण करता है, उसकी ऊर्जा ज़रूरतें बढ़ती रहेंगी। परिणामस्वरूप, भारत के लिए तेल और गैस उत्पादक देशों का महत्त्व जल्द ही कम नहीं होगा और भारत को ऊर्जा संसाधनों को तेजी से आगे बढ़ाने और आपूर्ति में विविधता लाने की आवश्यकता होगी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के बीच सम्बंधों के साथ-साथ ईरान की परमाणु महत्त्वाकांक्षाओं पर इन देशों की साझा चिंता में पारस्परिक मूल्य है। तदनुसार, दिल्ली ने पश्चिमी चिंताओं के जवाब में ईरान में अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को छोड़ने की कुछ इच्छा प्रदर्शित की है और तेहरान के साथ सैन्य सम्बंधों से परहेज किया है। फिर भी अमेरिकी चिंताओं के प्रति यह प्रतिक्रिया संभवतः भारतीय उद्देश्यों और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए चल रहे अभियान तक सीमित होगी। ईरान भारत की ऊर्जा मांग को पूरा करने, देश के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने और अपने कुछ क्षेत्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने में मदद कर सकता है। इस सम्बंध के लाभ वर्तमान में चीन के एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति और ऊर्जा संसाधनों के प्रतियोगी के रूप में उभरने से बढ़ रहे हैं। इस प्रकार, भारत के लिए ईरान के महत्त्व को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस गतिशीलता को देखते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत समान रूप से भारत की ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक समाधान विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समावेशी वार्ता से लाभान्वित हो सकते हैं।

इस प्रकार घरेलू और क्षेत्रीय मुद्दे ईरान के साथ बातचीत के भारत के लिए महत्त्व को बढ़ाते हैं और इन मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी क्योंकि तालिबान हाल ही में अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अफगानिस्तान में फिर से तेजी से उभर कर आ रहा है।

9.2 भारत-अमेरिका संबंध

२००४ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक समझौते की औपचारिकता ने भारत की विदेश नीति में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। यह घटना १९९८ में किए गए भारत के परमाणु परीक्षणों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा व्यक्त की गई सर्वसम्मत निंदा के विपरीत थी। भारत के साथ-साथ पाकिस्तान को अपने बैलिस्टिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को समाप्त करते हुए बिना किसी देरी के एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, सितंबर २००१ तक, अमेरिका ने दोनों देशों के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंध अपनाए, विदेशी सहायता को निलंबित कर दिया और अमेरिकी प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को रोक दिया।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

अमेरिका के साथ साझेदारी स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित भारतीय प्रतिनिधियों ने सफल राजनयिक पहलों की एक शृंखला शुरू की। मार्च २००० में बिल क्लिंटन की भारत यात्रा १९७८ के बाद से किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल के दौरान, कोंडोलीजा राइस और उनके समकक्ष ब्रजेश मिश्रा के बीच नियमित बैठकों के कारण जनवरी २००४ में 'रणनीतिक साझेदारी में अगले कदम' को अपनाया गया।

१८ जुलाई, २००५ को भारत और अमेरिका ने नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शासन में भारत के एकीकरण का रास्ता खोल दिया। वास्तव में, सितंबर २००८ में, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) ने परमाणु व्यापार में शामिल होने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था जो १९७४ में अपने पहले परमाणु परीक्षण के बाद लगाया गया था। इस रणनीतिक सम्बंध का अंतिम चरण २००८ में १२३ समझौते पर हस्ताक्षर करना था, जिसमें अमेरिका ने भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध किया था (state.gov, 2008)[47] इस समझौते ने भारत को एकमात्र देश के रूप में मंजूरी दे दी है, जिसे एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना वैश्विक नागरिक परमाणु व्यापार का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई है।

साथ ही ईरान के साथ भारत के सम्बंध अमेरिका और ईरान के बीच एक उपयोगी पुल साबित हो सकते हैं। इन सम्बंधों पर अंकुश लगाने के लिए ज़ोर देने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान तक पहुँचने में एक प्रमुख वार्ताकार के रूप में भारत की क्षमता पर विचार करने में लाभ मिल सकता है। यह विशेष रूप से अफगानिस्तान के सम्बंध में कहा जा सकता है जहाँ तीनों देशों के बीच हितों का एक महत्वपूर्ण अभिसरण है। यहाँ तक कि सीमित सहयोग भी एशियाई भू-राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से बदल देगा और संयुक्त राज्य अमेरिका को सैन्य जिहादी परिसर से उभरने वाली नकारात्मक क्षेत्रीय बाह्यताओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक मेल-मिलाप भी भारत के हित में है और नई दिल्ली एक वार्ताकार के रूप में एक अद्वितीय स्थान धारण कर सकती है, यह देखते हुए कि उसे अमेरिका और ईरानी दोनों सरकारों का विश्वास प्राप्त है (पंत और सुपर, 2013: 19)।[48]

10. निष्कर्ष

इस प्रकार शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत की ईरान नीति ने चतुर रणनीतिक लचीलापन दिखाया है। अपने बहु-स्तरीय दृष्टिकोण के माध्यम से, नई दिल्ली ऊर्जा सुरक्षा, अफ़गानिस्तान की स्थिरता और यूरेशियाई संपर्क जैसे प्रमुख हितों की रक्षा करने में सफल रही है और यह बिना किसी एकतरफ़ा गठबंधन के लिए बाध्य हुए हासिल किया गया है। १९९१ के बाद से साझा हितों के उभार से लेकर २०१६ के चाबहार समझौतों और ईरान के २०२३ के एससीओ में शामिल होने के लिए भारत ने लगातार उलझाव पर स्वायत्तता को प्राथमिकता दी है फिर भी हाल ही के घटनाक्रम ने रुके हुए बुनियादी ढांचे और अस्थिर तेल प्रवाह सहित कमजोरियों को उजागर किया है। अंततः यह नीति भारत के सैद्धांतिक लचीलेपन को मज़बूत करती है एवं संभावित विपरीत परिस्थितियों को अवसर के गलियारों में बदल देती है, हालांकि इसकी दीर्घकालिक प्रभावकारिता एक टूटती वैश्विक व्यवस्था में जोखिम प्रबंधन पर निर्भर करती है।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

11. लेखक/लेखकों का योगदान

लेखक पुष्टि करते हैं कि उनका किसी ऐसे समूह या संस्था से कोई संबंध या जुड़ाव नहीं है जो इस पांडुलिपि में शामिल विषयों या संसाधनों के लिए वित्तीय या गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करता हो।

12. हितों का टकराव

लेखकों ने इस लेख के शोध, लेखन और/या प्रकाशन के संबंध में किसी भी संभावित हितों के टकराव की घोषणा नहीं की है।

13. साहित्यिक चोरी नीति

सभी लेखक घोषणा करते हैं कि साहित्यिक चोरी, कॉपीराइट और नैतिक मामलों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन का सभी लेखक ध्यान रखेंगे। उपरोक्त मामलों के लिए पत्रिका और संपादक उत्तरदायी नहीं होंगे।

14. वित्तपोषण के स्रोत

लेखकों को शोध के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली।

सन्दर्भ सूची

ओलापल्ली, डी. और राजगोपालन, आर. (2012) भारत: एक अस्पष्ट शक्ति के विदेश नीति परिप्रेक्ष्य, एच.आर. नौ और डी. ओलापल्ली (संपादक) महत्वाकांक्षी शक्तियों के विश्वदृष्टिकोण: चीन, भारत, ईरान, जापान और रूस में घरेलू विदेश नीति वाद-विवाद, न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 73-113

कपूर, डी. (2009) जनमत और भारतीय विदेश नीति, इंडिया रिव्यू, 8(3): 286–305. doi: 10.1080/14736480903116818

कुमार, वी. (2016). भविष्य की दिशाएँ। [ऑनलाइन] उपलब्ध: http://www.futuredirections.org.au/publication/india-iran-relations-belated-re-start/ [19 दिसंबर 2016 को अभिगमित]

कुमार, वी. (2016). भविष्य की दिशाएँ। [ऑनलाइन] उपलब्ध: http://www.futuredirections.org.au/publication/india-iran-relations-belated-re-start/ [19 दिसंबर 2016 को अभिगमित]

गार्जियन, टी. (2016). भारत ईरानी बंदरगाह चाबहार में निवेश करेगा। [ऑनलाइन] उपलब्ध: https://www.theguardian.com/world/2016/may/23/india-invest-500m-iran-port-chabahar-modi-transit-accord-afghanistan [19 दिसंबर 2016 को अभिगमित]

गोल्डस्टीन, जे. (2006). अंतर्राष्ट्रीय संबंध (दूसरा). दिल्ली: पियर्सन एजुकेशन और बाबा बरखा.

ग्रीर, एल. और बैटमैनघेलिड्ज, ई. (2020) बराबरी वालों में आखिरी: क्षेत्रीय संदर्भ में चीन-ईरान साझेदारी, सामयिक पेपर श्रृंखला 38, विल्सन सेंटर, सितंबर, www.wilsoncenter. org/publication/last-among-equals-china-iran-partnership-regional-context

चौधरी, डी.आर. (2019) ईरान के साथ भारत के संबंध किसी तीसरे देश से प्रभावित नहीं हैं: विदेश मंत्रालय, इकोनॉमिक टाइम्स, 4 जुलाई, https://economictimes.indiatimes.com/news/politicsand-nation/indias-ties-with-iran-not-influenced-by-any-3rd-country-mea/ articleshow/70066206.cms?from=mdr

चौबे, एस. (2017) ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने दो हफ़्तों में दो बार कश्मीर मुद्दा उठाया, इंडिया टुडे, 5 जुलाई, www.indiatoday.in/world/story/irans-supreme-leaderkhamenei-rakes-up-kashmir-bogey-twice-in-two-weeks-1022519-2017-07-05.

ज़फ़र, डी. ए. (2016) उत्तर-दक्षिण गलियारा मध्य एशिया और यूरोप को भारत के करीब लाता है। नई दिल्ली: भारतीय विश्व मामलों की परिषद।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

ब्रजगोपाल , प्रोफ़ेसर मोहम्मद शाहिद , (2025),

शीत युद्ध के बाद भारत की ईरान नीति: संतुलन, चुनौतियाँ और रणनीतिक स्वायत्तता

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड रिव्यूज़, 4(3), 127-141.

ज़रगर, अफ़शिन. (2007). भारत-ईरान संबंधों में एकीकरण और विघटन, तेहरान: मध्य एशिया और काकेशस जर्नल.

डेवलिन, के. (2019) भारत में जनमत का एक नमूना, प्यू रिसर्च सेंटर, www. pewresearch.org/global/2019/03/25/a-sampling-of-public-opinion-in-india/

तस्नीम न्यूज़ एजेंसी (2020) भारत के कश्मीर में मुसलमानों ने अमेरिका द्वारा ईरान के जनरल सुलेमानी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, 3 जनवरी, www.tasnimnews.com/en/ news/2020/01/03/2173673/muslims-in-india-s-kashmir-protest-against-uskilling-of-iran-s-gen-soleimani-video

तिरुपति, आर. (2014) पुस्तक के आगे। आर. सिद्दा (पृष्ठ vii) में, भारत और ईरान के समकालीन संबंध। हैदराबाद: एलाइड पब्लिशर्स

द वीक (2019) ईरान ने ज़ब्त किए गए टैंकर से सात भारतीय बंदियों को रिहा किया: जहाज़ मालिक, 4 सितंबर, www.theweek.in/news/world/2019/09/04/iran-releases-sevenindian-captives-from-seized-tanker-ship-owner.html

नारायणन कुट्टी, एस. (2014) अफ़गानिस्तान में ईरान के निरंतर हित, द वाशिंगटन क्वार्टरली, 37(2): 139–56. doi: 10.1080/0163660X.2014.926214

नारायणन कुट्टी, एस. (2016) ईरान की बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ: भारत, चीन प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? आरएसआईएस टिप्पणी, 22 जनवरी, www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co16014-iransinfrastructure-projects-india-china competing/.

नारायणन कुट्टी, एस. (2019) मतभेदों से निपटना: भारत-अमेरिका संबंधों में ईरान कारक, एशिया नीति, 26(1): 95–118. doi: 10.1353/asp.2019.0014

नासिरपुर, जी. आर. (2016). ईरान-भारत गैस पाइपलाइन.

पंत हर्ष वी. और सुपर जूली एम. (2013) प्रतिद्वंद्वियों को संतुलित करना: ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भारत की कड़ी एशियाई नीति, अंक 15।

पंत, एच.वी., अय्यर, पी., कपूर, एन., तिर्की, ए. और बोम्माकांति, के. (2021) ओआरएफ विदेश नीति सर्वेक्षण 2021: युवा भारत और विश्व, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।

पालीवाल, ए. (2017) मेरे दुश्मन का दुश्मन: सोवियत आक्रमण से लेकर अमेरिकी वापसी तक अफ़ग़ानिस्तान में भारत, न्यूयॉर्क: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

पेरी, डी. (2018) चाबहार बंदरगाह परियोजना में ईरान के कारण देरी हुई: जयशंकर, द हिंदू, 19 जुलाई, https://www.thehindu.com/news/national/chabahar-port-project-delayeddue-to-iran jaishankar/article24455469.ece.

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (2017) डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम न करें, उनका विश्लेषण करें: एस जयशंकर, 14 फरवरी, https://timesofindia.indiatimes.com/india/dont-demonise-donaldtrump-analyse-him-s jaishankar/articleshow/57145060.cms

बरज़ेगर, के. (2014) तालिबान-उत्तर अफ़ग़ानिस्तान में ईरान की विदेश नीति, द वाशिंगटन क्वार्टरली, 37(2): 119–37. doi: 10.1080/0163660X.2014.926213

बसरूर, आर. और सुलिवन डी एस्ट्राडा, के. (2017) राइजिंग इंडिया: स्टेटस एंड पावर, लंदन: राउटलेज।

बसु, एन. (2020) भारत एक बड़ा देश है, उसे अमेरिका के साथ तनाव कम करने में भूमिका निभानी चाहिए: ईरान के मंत्री जवाद ज़रीफ़, द प्रिंट, 15 जनवरी, https://theprint.in/diplomacy/ भारत-बड़ा-देश-हमारे-साथ-तनाव-को-निवारण-में-भूमिका-निभानी-चाहिए-ईरान-मंत्री-जवाद-ज़रीफ़/349842.

ब्रिटिश पेट्रोलियम, आर.ओ.टी.डब्ल्यू. (2016) वार्षिक रिपोर्ट। लंदन: विश्व ऊर्जा सांख्यिकी समीक्षा बीपी पी.एल.सी.

भारत की जनगणना (2011) धर्म संबंधी आँकड़े, नई दिल्ली: महापंजीयक कार्यालय और जनगणना आयुक्त

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

ब्रजगोपाल , प्रोफ़ेसर मोहम्मद शाहिद , (2025),

शीत युद्ध के बाद भारत की ईरान नीति: संतुलन, चुनौतियाँ और रणनीतिक स्वायत्तता

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड रिव्यूज़, 4(3), 127-141.

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (1949) सुरक्षा परिषद में ईरान द्वारा भारत के विरुद्ध मतदान के संबंध में कथित रिपोर्ट (एमईए, 4(25)-आईए/49), 18 दिसंबर।

महाजा, एम. (2016). ईरान, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। [ऑनलाइन] उपलब्ध: https://www.inshorts.com/news/iran-overtakes-saudi-arabia-as-indias-top-oil-supplier-1479383529798 [19 दिसंबर 2016 को अभिगमित]।

मुखर्जी, आर. (2020) अराजकता एक अवसर के रूप में: भारत की व्यापक रणनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व व्यवस्था, समकालीन राजनीति, 26(4): 420–38. doi: 10.1080/13569775.2020.1777040

मेहदूदिया, एस. (2012) ईरान के खिलाफ अमेरिकी और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों से बाध्य नहीं: भारत, द हिंदू, 25 जनवरी, www.thehindu.com/news/national/Not-bound-by-U.S.-andEU-sanctions-against-Iran-India/article13380756.ece.

मोहन, जी. (2020) दिल्ली में लाल झंडे वाला अमेरिका विरोधी मार्च, कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की मांग करता है। सुलेमानी की हत्या, इंडिया टुडे, 7 जनवरी, www.indiatoday.in/india/story/anti-usprotest-march-in-delhi-after qassem-soleimani-killing-1634705-2020-01-07.

मोहन, सी.आर. (2017) भारत ट्रंप की दुनिया में कैसे बातचीत कर सकता है, इंडियन एक्सप्रेस, 25 दिसंबर, https://indianexpress.com/article/opinion/columns/how-india-cannegotiate-donald-trumps-world-narendra-modi 4997456/.

मोहन, सी.आर. (2020) भारत के भू-राजनीतिक हित उदारवादी अरब केंद्र के साथ घनिष्ठ रूप से संरेखित हैं, इंडियन एक्सप्रेस, 18 अगस्त, https://indianexpress.com/article/ opinion/columns/narendra-modi-arab-gulf-countries-middle-east-relations-craja-mohan-6558876/.

येगानेहशाकिब, आर. (2016). अलमॉनिटर. [ऑनलाइन] उपलब्ध: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/iran-india-oman-gas- pipeline-meidp-vs-tapi.html [20 नवंबर 2016 को एक्सेस किया गया]

रघुरामपतरुनी (2014) भारत-ईरान व्यापार संबंधों की संभावनाएँ और संभावनाएँ। आर. सुड्डा (पृष्ठ 161-165) समकालीन संबंधों में भारत-ईरान। हैदराबाद: एलाइड पब्लिशर्स।

वटंका, ए. (2015) ईरान और पाकिस्तान: सुरक्षा, कूटनीति और अमेरिकी प्रभाव, लंदन: ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग।

वर्मा, आर. (2022) अमेरिका-तालिबान शांति समझौता और क्षेत्रीय शक्तियाँ संभावित विघ्नकर्ता: ईरान एक केस स्टडी के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, 59: 260–79. doi: 10.1057/s41311-021-00302-7.

वर्मा, एन. (2016). रिटर्स, लौटने वाले खरीदार। [ऑनलाइन] उपलब्ध: http://in.reuters.com/article/india-iran-oil importsidINKBN13C0Z3?utm_source=inshorts&utm_medium=inshorts_full_article&utm_campaign=inshorts_full_article [19 दिसंबर 2016 को देखा गया]।

विकिपीडिया, (2016). ईरान में तेल भंडार। [ऑनलाइन] उपलब्ध: https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_reserves_in_Irann[19 दिसंबर 2016 को अभिगमित]

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License